राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

एसबी आपराधिक विविध स्थगन आवेदन संख्या 2267/2024

में

एसबी आपराधिक अपील संख्या 1798/2022

मोहित कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी कोरर थाना कोतवाली डीग, जिला भरतपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं)के लिए : श्री विनय पाल यादव
प्रतिवादी(ओं)के लिए : श्री इमरान खान, पीपी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

02/04/2024

प्रकाशनीय

1. आवेदक अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी मामले, अजमेर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय पर रोक लगाने के लिए दायर विविध स्थगन आवेदन प्रस्तुत है। निर्णय दिनांक 03.09.2022 के

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

अनुसार, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे 5,000 /- रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. आवेदक-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 307 और 120-बी और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता को आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत आरोप को छोड़कर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और उसे दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पिस्तौल की बरामदगी हुई थी, लेकिन उसे एक खुले स्थान से बरामद किया गया था जो अपीलकर्ता के विशेष कब्जे में नहीं था। वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की सजा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 के आदेश द्वारा पहले ही निलंबित कर दी गई है। वकील ने दलील दी कि मुकदमे और इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने ईसीजी तकनीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया और दिनांक 15.03.2024 के आदेश द्वारा उसका चयन और नियुक्ति की गई। वकील ने दलील दी कि अब दोषसिद्धि का निर्णय

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

अपीलकर्ता के ईसीजी तकनीशियन के पद पर नियुक्ति पाने में आड़े आएगा, इसलिए इन परिस्थितियों में अपील के निपटारे तक उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:

1. राहुल गांधी बनाम पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी एवं अन्य **(**अपील हेतु विशेष अनुमति **(** सीआरएल **)** संख्या **8644/2023)**

2. नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य **2007 (2)** एससीसी **574** में रिपोर्ट किया गया

3. अर्पित जैन बनाम राजस्थान राज्य **(**एसबी आपराधिक स्थगन संख्या **3278/2018)**

4. डॉ. मंजू डुलेट एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य **(**एसबी आपराधिक विविध स्थगन आवेदन संख्या **1365/2019)**

5. सुभाष खोलिया बनाम राजस्थान राज्य **(**एसबी आपराधिक विविध स्टे आवेदन संख्या **1602/2017)**

3. वकील ने दलील दी कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सजा पर रोक लगाने के लिए उचित आदेश पारित किए जाएं।

4. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि ईसीजी

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

तकनीशियन के पद पर अपीलकर्ता का चयन मात्र दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आधार नहीं है। वकील ने तर्क दिया कि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोकी जा सकती है और अपीलकर्ता अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई विशेष मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है, इसलिए इन परिस्थितियों में, आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

5. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. सबसे पहले, उन आवश्यक मानदंडों को रेखांकित करना आवश्यक है जिनकी सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि के निलंबन का मामला बनाया जा सकता है। धारा 389(1) अपीलीय न्यायालय को अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निलंबन या दोषसिद्धि के आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 389(1) की सटीक भाषा की जाँच करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है , जिसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है:

> "धारा 389(1) – किसी दोषी व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने पर, अपीलीय न्यायालय, उसके द्वारा लिखित

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश दे सकता है कि जिस सजा या आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसका निष्पादन निलंबित कर दिया जाए और, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा कर दिया जाए।"

7. प्रावधान की स्पष्ट भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय में स्पष्ट रूप से अपील के तहत सजा या दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने और कैद दोषी को जमानत देने की शक्ति निहित है, जिसके लिए लिखित में कारण बताना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर इस मुद्दे की व्यापक जांच की है, और सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि के निलंबन के लिए व्यापक मापदंडों का निर्धारण किया है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए, प्राथमिक कारक जिन पर गौर किया जाना है, वे उस विशिष्ट मामले के अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियां होंगी, जहां ऐसी दोषसिद्धि को रोकने में विफलता से अन्याय या अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। अपरिवर्तनीय परिणामों की अवधारणा ही कारकों पर केंद्रित होती है , जिसमें व्यक्ति का आपराधिक इतिहास, अपराध की गंभीरता और इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव शामिल है,

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू **(सुप्रा)** के मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "इसलिए, कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित या स्थगित कर सकता है। लेकिन दोषसिद्धि पर स्थगन चाहने वाले व्यक्ति को अपीलीय न्यायालय का ध्यान विशेष रूप से उन परिणामों की ओर आकर्षित करना चाहिए जो दोषसिद्धि पर स्थगन न दिए जाने पर उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक न्यायालय का ध्यान दोषसिद्धि के कारण होने वाले विशिष्ट परिणामों की ओर आकर्षित नहीं किया जाता, तब तक दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा, मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर, दुर्लभ मामलों में दोषसिद्धि पर स्थगन का सहारा लिया जा सकता है।"

9. इसी प्रकार, **1995 (2)** एससीसी **513** में दर्ज रामा नारंग बनाम रमेश नारंग एवं अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> "यह हमें इस प्रश्न पर ले जाता है कि क्या संहिता की धारा 389(1) का दायरा अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करने तक विस्तारित है। जैसा कि पहले कहा गया है, यदि दोषसिद्धि के आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम की धारा 267 में उल्लिखित प्रकार की कुछ-अयोग्यता उत्पन्न

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

होती है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम संहिता की धारा 389(1) को एक संकीर्ण अर्थ दें जो न्यायालय को एक उपयुक्त मामले में उस आशय का आदेश देने से रोकता है। धारा 374 के तहत अपील अनिवार्य रूप से दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध है क्योंकि सजा का आदेश केवल उसका परिणामी है; यद्यपि सजा के आदेश को भी स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जा सकती है यदि वह कठोर और स्थापित दोष के अनुपात से असंगत है। इसलिए, जब धारा 374 के तहत अपील की जाती है, तो अपील दोषसिद्धि और सजा दोनों के विरुद्ध होती है और इसलिए, हमें संहिता की धारा 389(1) की संकीर्ण व्याख्या करने का कोई कारण नहीं दिखता ताकि इसे दोषसिद्धि के आदेश तक विस्तारित न किया जा सके। यद्यपि वर्तमान मामले में वह मुद्दा पृष्ठभूमि में चला जाता है। क्योंकि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं यदि संहिता की धारा 389(1) में यह शक्ति नहीं पाई जाती। इसलिए, हमारी राय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह मानना सही नहीं था कि दिल्ली उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था यदि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता कि दोषसिद्धि के आदेश के संचालन को रोकने के लिए कानून में कोई अन्य प्रावधान नहीं है। किसी उपयुक्त मामले में यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित या स्थगित करने की आवश्यकता है ताकि दोषी व्यक्ति किसी अन्य कानून में प्रदान की गई किसी निश्चित अयोग्यता से ग्रस्त न हो, तो

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

> वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है क्योंकि अन्यथा हुई क्षति को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है; कंपनी अधिनियम की धारा 267 द्वारा हुई और प्रभावी की गई अयोग्यता को बाद की किसी तारीख को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन दोषसिद्धि के आदेश के निलंबन पर स्थगन देते समय न्यायालय को इसके पक्ष और विपक्ष की जांच करनी चाहिए और यदि वह संतुष्ट महसूस करता है ऐसे आदेश के विरुद्ध, वह ऐसा कर सकता है और ऐसा करते समय, यदि वह इसे उचित समझे, तो ऐसी शर्तें लगा सकता है जो शेयरधारकों के हितों और कंपनी के व्यवसाय की रक्षा के लिए उपयुक्त समझी जाएं।

10. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या **3838/2023** में माना है कि किसी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने के लिए, प्राथमिक कारक जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे उस विशिष्ट मामले के अजीब तथ्य और परिस्थितियां होंगी, जहां इस तरह की सजा को रोकने में विफलता से अन्याय या अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे और इसे पैरा 11 में निम्नानुसार माना गया है:

> "11. प्रावधान की स्पष्ट भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय न्यायालय में स्पष्ट रूप से अपील के तहत सजा या दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने और कैद अपराधी को जमानत देने की शक्ति निहित है,

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

> जिसके लिए लिखित में कारण बताना अनिवार्य है। इस न्यायालय ने कई अवसरों पर इस मुद्दे की व्यापक जांच की है, और सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि के निलंबन के लिए व्यापक मापदंडों का निर्धारण किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए, जिन प्राथमिक कारकों पर गौर किया जाना है, वे उस विशिष्ट मामले के अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियां होंगी, जहां ऐसी दोषसिद्धि को रोकने में विफलता से अन्याय या अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। अपरिवर्तनीय परिणामों की धारणा ही कारकों पर केंद्रित होती है , जिसमें व्यक्ति का आपराधिक इतिहास, अपराध की गंभीरता और इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव शामिल है,

11. रविकांत पाटीला बनाम सर्वभूमा एस. बागली के **2007 (1)** एससीसी **673** में दिए गए फैसले के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल अंसारी (सुप्रा) के पैरा 15 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> 15. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर यह राय व्यक्त की है कि दोषसिद्धि के आदेश पर रोक के संदर्भ में, जब अपरिवर्तनीय परिणाम हों, सीआरपीसी की धारा 389(1) की संकीर्ण व्याख्या करने का कोई कारण नहीं है। निस्संदेह, रविकांत पाटिल बनाम सर्वभूमा एस. बागली , 6 में कहा गया है कि दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश नियम नहीं, बल्कि अपवाद होना चाहिए और मामले के तथ्यों के आधार पर दुर्लभ मामलों में ही इसका सहारा लिया जाना चाहिए।

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

> हालाँकि, जहाँ दोषसिद्धि को लागू रहने देने से अपूरणीय क्षति होगी और जहाँ दोषी को किसी भी प्रकार की आर्थिक या अन्य क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती, यदि उसे बाद में बरी कर दिया जाता है, तो यह अपने आप में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करता है। ऊपर उल्लिखित विशिष्ट मानदंडों को वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लागू करने के बाद, हमारा सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता का मामला, आंशिक रूप से ही सही, उसकी दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश का समर्थन करता है।

12. वर्तमान मामले की बात करें तो, अपीलकर्ता पर विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(V) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 शामिल हैं। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत आरोप को छोड़कर अन्य सभी आरोपों से पहले ही बरी कर दिया गया है और उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों के न्यायालय, अजमेर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय को राज्य और साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर करके चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उपरोक्त आरोपों से अपीलकर्ता को बरी करने का निर्णय अंतिम हो गया है। इस तथ्य

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

पर कोई विवाद नहीं है कि इस अपील के लंबित रहने के दौरान , अपीलकर्ता का चयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 15.03.2024 के आदेश द्वारा ईसीजी तकनीशियन के पद पर किया गया था। चूँकि अपीलकर्ता को एक छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसकी दोषसिद्धि उसकी नियुक्ति के आड़े आएगी और यदि अपील के निपटारे तक उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो उसे नियुक्ति खोने के अपरिवर्तनीय परिणाम भुगतने होंगे। आवेदक एक युवा लड़का है और इस मामले में उसकी दोषसिद्धि के कारण उसका पूरा भविष्य दांव पर है। यदि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को लागू रहने दिया जाता है, तो इससे अपूरणीय क्षति होगी और यदि वह सेवा पाने का अवसर खो देता है और बाद में बरी हो जाता है, तो उसके लिए धन या अन्यथा क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी, जो अपने आप में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न करता है। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में ऊपर उल्लिखित विशिष्ट मानदंडों को लागू करने के बाद, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि अपीलकर्ता का मामला उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आदेश का समर्थन करता है।

13. उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलकर्ता द्वारा दायर स्थगन आवेदन स्वीकार किया जाता है। विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)

जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, अजमेर द्वारा पारित दिनांक 03.09.2022 के निर्णय से उत्पन्न अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, अपील के निपटारे तक स्थगित रहेगी।

(अनूप कुमार ढांड) ,जे

कुडी/70

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(29/05/2025 को 01:30:05 PM पर डाउनलोड किया गया)